



सत्यमेव जयते

कस्लूम्स मरियु सेंट्रल टाक्स कमीशनर कार्यालय (अपील्स-II)
7th Floor, GST Bhavan, L.B. Stadium Road, Basheerbagh, Hyderabad, Telangana, PIN-500004
केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर आयुक्त का कार्यालय (अपील्स-II)
सातवा तल, जी. एस. टी. भवन, एल. बी. स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद, पिन - 500004

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS & CENTRAL TAX
APPEALS-II COMMISSIONERATE, HYDERABAD

7th Floor, GST Bhavan, L.B. Stadium Road, Basheerbagh, Hyderabad, Telangana, PIN-500004.

Ph: 040-23234219 / e-Mail: cgst.hydappeals2@gov.in

Appeal No. 96/2024-(SC)DGST

OIO No. 107/2023-24-Sec-Adjn-ADC(ST) dated 27th March, 2024

DIN- 20241256DN0000116939

अपीलआदेशसं: ORDER-IN-APPEAL No. HYD-GST-SC-AP2-384-24-25

Dated 11th December, 2024

जारीकर्ता : श्री. मनोज कुमार रजक, आयुक्त, सीमा शुल्क व केन्द्रीय कर (अपील्स-II)
Passed by: Shri Manoj Kumar Rajak, Commissioner of Customs & Central Tax
(Appeals-II)

उद्देशिका / PREAMBLE

1	जिस व्यक्ति को यह प्रति जारी की जाती है, उस व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए निशुल्क दी जाती है। This copy is granted free of cost for the private use of the person to whom it is issued.
2.	इस आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 110 के साथ पठित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 112 (1) के तहत इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 109 के तहत गठित उपयुक्त अपीलीय न्यायाधिकरण के राज्य / क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के खंड पीठ में उन मामलों में, जिनमें 'अपूर्ति की जगह' विवाद-ग्रस्त विषयों में से एक न हो, अपील दायर कर सकता है। जहां 'अपूर्ति की जगह' विवादित मामलों में से एक है, अपील, उपरोक्त धारा 109 के तहत गठित राष्ट्रीय / क्षेत्रीय खंडपीठ के समक्ष दायर की जाए। जिस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा रही है उसे अपीलकर्ता को संप्रेषित करने की तिथि से 3 (तीन) माह के अंदर अपील जीएसटी एपीएल-05 फॉर्म में दायर की जानी चाहिए। आदेश की एक प्रमाणित प्रति, यदि लागू हो तो नियम 110 (5) के अंतर्गत विहित शुल्क तथा अन्य संगत दस्तावेज संलग्न करते हुए, अपील पर नियम 26 के तहत विनिर्दिष्ट तरीके से हस्ताक्षर किए जाएं। Any person aggrieved by this order, may under Section 112(1) of the Central Goods and Services Tax (CGST) Act 2017, read with Rule 110 of the CGST Rules, 2017; file an appeal electronically or otherwise, to the appropriate State / Area Bench of the Appellate Tribunal constituted under Sec 109 of the CGST Act 2017 in cases not involving 'place of supply' as one of the disputed issues. Where the 'place of supply' is one of the disputed issues, the appeal shall be filed with the National / Regional bench constituted under the said Sec 109. The appeal should be filed in Form GST APL-05 within 3(three) months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal. The appeal shall be signed in the manner specified under Rule 26, enclosing a certified copy of the order, the prescribed fee under Rule 110(5) if applicable, and any other relevant documents.
3.	वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 111 के साथ पठित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 112 (3) के तहत आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 109 के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के राज्य / क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के खंड पीठ में उन मामलों में, जिनमें 'अपूर्ति की जगह' विवाद-ग्रस्त विषयों में से एक न हो, अपील दायर कर सकता है। जहां 'अपूर्ति की जगह' विवादित मामलों में से एक है, अपील, उपरोक्त धारा 109 के तहत गठित राष्ट्रीय / क्षेत्रीय खंडपीठ के समक्ष दायर की जाए। जिस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा रही है उसे जारी करने की तिथि से 6 (छः) माह के अंदर अपील जीएसटी एपीएल -07 फॉर्म में दायर की जानी चाहिए। अपील के साथ आदेश की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संगत दस्तावेज संलग्न हो। विभागीय अपील के प्रत्याक्षेप, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 112 (5) के साथ पठित नियम 110 (2) के अनुसार जीएसटी एपीएल -06 फॉर्म में इसके सम्प्रेषण के 45 दिनों के अंदर दायर किए जाएं और इस पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट तरीके से हस्ताक्षर किए जाएं। The officer authorized by the Commissioner under Sec 112(3) of the CGST Act 2017, read with Rule 111 of the CGST Rules, 2017; file an appeal electronically or otherwise, to the State / Area Bench of the Appellate Tribunal constituted under Sec 109 of the CGST Act 2017 in cases not involving 'place of supply' as one of the disputed issues. Where the 'place of supply' is one of the disputed issues, the appeal shall be filed with the National / Regional bench constituted under the said Sec 109. The appeal should be filed in Form GST APL-07 within 6 (six) months of the date of issuance of the disputed order. The appeal shall enclose a certified copy of the order, and any other relevant documents. The cross objections to the departmental appeal shall be filed within 45 days of communicating it, in Form GST APL-06 in terms of Rule 110(2) read

	with Sec 112(5) of the CGST Act 2017 and signed in the manner specified in Rule 26.
	रेवेन्यू बार एसोसिएशन के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के मददेनजर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है। v. भारत संघ और इसलिए अपील उस तारीख से तीन महीने के भीतर दायर नहीं की जा सकती जिस दिन आदेश के खिलाफ अपील की मांग की गई है। अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए, सरकार ने परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का नौवां निवारण) आदेश, 2019 दिनांक 03.12.2019 जारी किया है। उक्त आदेश के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि ट्रिब्यूनल में अपील आदेश के संचार की तारीख या जिस तारीख को राष्ट्रपति या राज्य अध्यक्ष, के रूप में तीन महीने (सरकार द्वारा अपील के मामले में छह महीने) के भीतर की जा सकती है। अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय में प्रवेश करने की स्थिति में, जो भी बाद में हो।
	(ii) The appellate tribunal has not been constituted in view of the order by Madras High Court in case of Revenue Bar Assn. v. Union of India and therefore the appeal cannot be filed within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated. In order to remove difficulty arising in giving effect to the above provision of the Act, the Government, on the recommendations of the Council, has issued the Central Goods and Services Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019 dated 03.12.2019. It has been provided through the said Order that the appeal to tribunal can be made within three months (six months in case of appeals by the Government) from the date of communication of order or date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal enters office, whichever is later.
4.	धारा 112 (8) के अनुसार, धारा 112 (1) के तहत तब तक कोई अपील दायर नहीं की जाएगी जब तक अपीलकर्ता ने (ए) आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, फाइन, शुल्क व जुर्माना के उस अंश का, जो उसके द्वारा स्वीकार किया गया है तथा (बी) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है, से उत्पन्न धारा 107(6) के अंतर्गत प्रदत्त राशि के अतिरिक्त, विवादित कर की शेष राशि के 20% का पूर्ण भुगतान नहीं किया हो।
	In terms of Sec 112(8), no appeal shall be filed under Sec 112(1) unless the appellant has paid (a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him, and (b) a sum equal to 20% of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under Sec 107(6), arising from the said order, in relation to which the appeal has been filed.
5.(i)	धारा 112 (1) के तहत आवेदन पत्र के साथ रूपए 5 मूल्य (केवल पांच रुपये) का गैर न्यायिक न्यायालय शुल्क टिकट हो। नियम 110 (5) के साथ पठित धारा 112 (10) के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील / अपील प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ अधिकतम रु. पच्चीस हजार रुपये के अध्यक्षीन कर / इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रति एक लाख रुपये के लिए रु. एक हजार का शुल्क या कर या इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उसमें निर्धारित फाइन, शुल्क या जुर्माना लगाया जाए।
	The application under Sec 112(1) shall bear a non-judicial court fee stamp of value Rs.5 (Rupees Five only). In terms of Sec 112(10) read with Rule 110(5), an application for appeal / restoration of appeal before the Appellate Tribunal shall be accompanied by a fee of One thousand rupees for every one lakh rupees of tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined in the order appealed against, subject to a maximum of twenty-five thousand rupees
5.(ii)	उपरोक्त धारा 112 की उप धारा (5) में संदर्भित कुल प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा।
	No fee is payable in respect of the Memorandum of Cross Objections referred to in sub-sec (5) of Sec 112 ibid.
5.(iii)	धारा 112(3) के अंतर्गत, आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन के मामले में कोई शुल्क देय नहीं होगा।
	No fee is payable in case of an application filed by the officer authorized by the Commissioner to file an appeal under Sec 112(3).
6.	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में निहित उक्त एवं अन्य संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों और इनके तहत बनाए गए नियम / जारी की गई अधिसूचनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
	Attention is invited to the provisions governing these and other related matters, contained in the Central Goods & Services Act, 2017 and the rules made / notifications issued thereunder, for compliance.

Appellant	The Assistant Commissioner of Central Tax, Secunderabad CGST Division, Secunderabad CGST Commissionerate, Hyderabad.
Respondent	The Additional Commissioner of Central Tax, Secunderabad CGST Commissionerate, Hyderabad
Taxpayer Respondent	M/s. Alpine Estates, 5-4-187/3&4, II Floor, Soham Mansion, MG Road, Secunderabad – 500 003.

BRIEF FACTS OF THE CASE:

These proceedings arise out of appeal filed by the Assistant Commissioner of Central Tax, Secunderabad CGST Division, Secunderabad CGST Commissionerate (here-in-after referred to as "Appellant") against Order in Original No. 107/2023-24-Sec-Adjn-ADC(ST) dated 27th March, 2024 (here-in-after referred to as "Impugned Order"), passed by the Additional Commissioner of Central tax, Secunderabad CGST Commissionerate, Hyderabad (here-in-after referred to as "the Respondent"), against M/s. Alpine Estates, 5-4-187/3&4, II Floor, Soham Mansion, MG Road, Secunderabad – 500 003 (here-in-after referred to as "taxpayer respondent").

2. Demand notice was issued to the taxpayer respondent for non-payment of service tax towards provision of 'construction services' and the same was confirmed by the respondent and the appellate authority, however, the Hon'ble CESTAT, vide Final Order No.30699/2019 dated 09th June, 2019, has decided that service tax is payable on construction services rendered w.e.f. 01.07.2010 onwards only, and remanded the case to the respondent for arriving at the correct taxable value for the services rendered after 01.07.2010. The respondent has taken up the denovo proceedings and issued the impugned order, as per the directions of the Hon'ble CESTAT. Aggrieved by the impugned order the appellant filed the appeal, contending that the service tax is payable on services rendered prior to 01.07/2010 also, on the grounds that: -

- the taxpayer respondent is not covered by the situation explained in the Board's circular 108/02/2009-ST dated 29th January, 2009;
- reliance of the said circular by taxpayer respondent and CESTAT is not relevant; and
- the 'agreement for construction' shall be considered as 'works contract' and the taxpayer respondent is liable for payment of service tax on such services.

PERSONAL HEARING:

3. Shri. Lakshman Kumar K, Chartered Accountant appeared for personal hearing held on 10th December, 2024, and submitted counter submissions. He also submitted that the issues stated in the department appeal, do not have merits and requested to dismiss the same.

DISCUSSION AND FINDINGS:

4. I have gone through the statement of facts, ground of appeal filed by the appellant, counter submissions made by the taxpayer respondent and the submissions made during the personal hearings held in the case. The issue to be decided is as to

whether service tax is payable on constructions services rendered by the taxpayer respondent, before 01.07.2010.

5. Appellant contended that service tax on constructions services rendered by the taxpayer respondent, against the 'agreement of construction', prior to 01.07.2010, and further submitted that the Hon'ble CESTAT decision was accepted by the department on monetary limits and not on merits. Hon'ble CESTAT, after examination of the fact of the case, categorically decided that the services rendered prior to 01.07.2010 are not exigible to service tax and service tax is payable from 01.07.2010 only. The department also accepted the decision of the CESTAT, may be on monetary limits. Department having accepted the Hon'ble CESTAT decision, the impugned order is proper and legal, in as much as the same is issued, following the judicial discipline. I do not find any reason to interfere with the impugned order.

6. Accordingly, I pass the following order:-

ORDER

Appeal is dismissed.



To

(1) The Assistant Commissioner of Central tax,
Secunderabad CGST Division,
Secunderabad CGST Commissionerate,
Hyderabad.

(2) M/s. Alpine Estates,
5-4-187/3&4, II Floor,
Soham Mansion, MG Road,
Secunderabad – 500 003.

Copy Submitted to the Principal Chief Commissioner of Customs and Central Tax,
Hyderabad Zone, Hyderabad.

Copy to:

- The Commissioner of Central Tax, Secunderabad CGST Commissionerate,
GST Bhavan, Basheerbagh, Hyderabad.
- Master Copy / Office copy.

COMMISSIONER
आयुक्त

EMS SPEED POST
A/c. No: 1742
Customer ID: 200 000 1681

From
Office of the Commissioner of
Customs & Central Tax
Appeals-II Commissionerate
7th Floor, GST Bhavan, L.B. Stadium Road
Basheerbagh, Hyderabad-500 004.



Office of the Commissioner of
Customs & Central Tax
Appeals-II Commissionerate
7th Floor, GST Bhavan, L.B. Stadium Road
Bansalbagh, Hyderabad-500 004.



EMS SPEED POST
A/c. No: 1742
Customer ID: 200 000 1681

976

केवल आ.स.से पर
ON I.G.S. Only

स्पीड पोस्ट
SPEED POST

To,
M/s. Hiline Estates,
5-4-187/3 and 4,
II Floor, Goham Mansion,
M.G. Road, Secunderabad,
= 500003